Impact of religion on Indian politics

व्यापक अर्थ में इसका अर्थ सम्पूर्ण हिन्दू समाज के ही भीतर किसी सामाजिक-धार्मिक समुदाय के साथ संबध के रूप में लिया जाए तो सभी पार्टियों में किसी न किसी रूप में यह भावना अवश्य विद्यमान होती है ।

कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही है । केरल में ईसाई समुदाय के साथ कांग्रेस का ऐसा गठजोड रहा है कि इसे संकुचित दृष्टि से भी साम्प्रदायिकता कहा गया है । आज भारतीय राजनीति में धार्मिक संगठन शक्तिशाली दबाव समूहों की भूमिका निभा रहे हैं ।

ये धार्मिक संगठन शासन की नीतियों को समय-समय पर प्रभावित करते रहते है और अपने हितों के अनुकूल निर्णय पारित करवाने का प्रयत्न करते रहते है । उदाहरणार्थ, मुस्लिम धार्मिक संगठनों जैसे जमायते इस्लामी, उलमा-ए-हिन्द अमारते शरिया ने सरकारी नीतियों को प्रभावित कर अपने हितों में तीन महत्वपूर्ण बातों को मनवाया-प्रथम, उर्दू को संवैधानिक संरक्षण दिया गया ।

द्वितीय, अलीगढ विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक स्वरूप स्थापित किया जाए । तृतीय, मुस्लिम निजी कानून से सम्बन्धित कोई परिवर्तन न किया जाए । इसके विपरीत हिन्दू धार्मिक संगठन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाए, जिस कारण हिन्दुओं की आपत्ति व आलोचनाओं के बावजूद भी सरकार ने हिन्दू कोड बिल पारित कर दिया ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जो धार्मिक संगठन सरकारी नीतियो को प्रभावित करने में सफल हो जाते है वे अपने हित मे कानून पारित करवा सकते हैं । भारतीय राजनीति में कई बार अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के आधार पर पृथक् राज्यों की माँग की गई है । उदाहरण के लिए पजाब का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था । अभी भी पजाब धर्म के आधार पर ही 'खालिस्तान' की माँग कर रहा है ।

नागालैण्ड के ईसाईयों ने भी धर्म के आधार पर ही पृथक् राज्य की माँग की थी । राज्यो की राजनीति में भी धर्म और धार्मिक समुदायों ने अनेक तरह से प्रभाव डाला है, इसके अतिरिक्त धर्म एवं साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए भी घातक माने

जाते हैं । देश का विभाजन धार्मिक मतभेदों के कारण ही हुआ था और आज भी विघटनकारी तत्व सक्रिय है ।

मन्त्रिमण्डल निर्माण में भी धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता प्रदान की जाती है । केन्द्र एवं राज्यों मे मन्त्रिमण्डल बनाते समय हमेशा इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख सम्प्रदायी और धार्मिक विश्वासी वाले व्यक्तियों को उनमें प्रतिनिधित्व मिल जाए । केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल मे अल्पसख्यकों जैसे मुसलमानों, सिक्खों, ईसाईयों को हमेशा प्रतिनिधित्व दिया जाता है ।

भारत में चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दल एवं उनके नेता धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं । वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामी, पादरियों और साधुओं के साथ सांठ-गांठ की जाती है । अत: यही कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति मे धर्म एवं साम्प्रदायिकता का प्रभाव बढने से धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है ।

भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का लक्ष्य यह था कि धर्म को राजनीति से पृथक् रखा जाए लेकिन व्यवहार में धर्म का प्रभाव भारतीय जनता पर छाया हुआ है । आज भी राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र मे धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है । वास्तव में आज धर्म और सम्प्रदाय राजनीति का शोषण करने लगे हैं ।

साम्प्रदायिकता मानवता हेतु गम्भीर अभिशाप है और भारत जैसे देश मे तो यह और भी घातक है, क्योंकि भारत विविध धर्मों का देश है । साम्प्रदायिकता को दूर किया जा सकता है यदि सरकार ध्यान रखे कि देश में कोई भी एसा कार्य न होने पाए जिससे कि साम्प्रदायिकता बढे, सर्वत्र इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाए कि सब धर्मों के लोग मिल-जुलकर रोज मौन प्रार्थना करें, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों एवं आदर्शों का समावेश किया जाए, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा न की जाए, सरकार को भी हमेशा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हों ।

जाति, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय एवं भाषा के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव न किया जाए, विभिन्न सम्प्रदाय सरकार से अपने विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं । सरकार को इन सबके इस प्रभाव को केवल साम्प्रदायिकता के आधार पर ठुकराना होगा तथा भाषा के आधार पर भी सरकार को अपनी नीति ठीक करनी होगी ।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि हम भारतीय हैं, हमे इस बात पर गर्व है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं । इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है जिससे कि धर्म को राजनीति से हटाया जाए, किन्तु धर्म का प्रभाव व्यावहारिक रूप से भारतीय जनता के मन-मस्तिष्क से नहीं मिट पाया है ।

आज भी राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किये जाते हैं । राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल धर्म एवं सम्प्रदाय को राजनीतिक सफलता के लिए एक साधन के रूप मे अपनाते रहे है । साम्प्रदायिक झगडे भले ही छुटपुट और स्थानीय हों, लेकिन उनसे देश की बदनामी होती है और उसका लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कलंकित होता है क्योंकि साम्प्रदायिकता का उद्देश्य संकुचित हितो की रक्षा करना होता है ।

अत: राष्ट्रीय नेताओं पर यह दायित्व है कि वे समुदाय के सीमित तथा राष्ट्र के बृहत्तर हितो के मध्य सन्तुलन स्थापित करें, समुदाय को राष्ट्र में बदलें । भविष्य मे यह आशा व्यक्त की जा सकती है कि राजनीतिक चेतना एवं लोकतान्त्रिक आदर्शो एवं मूल्यो में वृद्धि होने से देश में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप भी निखरता जाएगा ।